

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च पैदावार, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त वाली फसलों की एक सौ 9 किस्में जारी की। ये किस्में 61 फसलों की हैं, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज शामिल हैं। इस बीच, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन फसलों से किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ पैदावार में इजाफा होगा और लागत घटेगी। उन्होंने बताया कि इन फसलों के बीज जलवायु अनुकूल हैं और खराब मौसम में भी बेहतर पैदावार दे सकते हैं। इसके अलावा ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर हैं।

नशा मुक्ति केन्द्र

प्रदेश सरकार सिरमौर जिले में पच्छाद उपमंडल के कोटला बड़ोग में राज्यस्तरीय आदर्श नशा मुक्ति व पुर्नवास केन्द्र स्थापित करेगी। ये केन्द्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करेगा और उन्हें समाज में फिर से एक खुशहाल व स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस नशा मुक्ति केन्द्र में 100 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस केन्द्र का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखना और राष्ट्र निर्माण में उनका सकारात्मक योगदान सुनिश्चित करना है। नशे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ रहे पीलिया के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल वसूलने जा रही है लेकिन पानी की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में पीलिया एक महामारी की तरह फैल रहा है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पीलिया के बढ़ते मामलों की सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि पेयजल आपूर्ति में किसी न किसी प्रकार की खामी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केवल सुविधाएं छीनने और महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और सरकार को जनसुविधाओं से कोई लेना-देना नहीं है।

शहीद

सिरमौर जिले में राजगढ़ क्षेत्र से संबंध रखने वाले लांस नायक प्रवीण शर्मा बीते कल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए। वे वन पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। शहीद प्रवीण शर्मा की पार्थिव देह कल सुबह चंडीगढ़ पहुंचेगी। जहां से पार्थिव देह को पैतृक गांव लाने के लिए सिरमौर प्रशासन द्वारा ऐम्बुलेंस का प्रबंध किया गया है। शहीद प्रवीण शर्मा का कल सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने लांस नायक प्रवीण शर्मा की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

हर घर तिरंगा

प्रदेश में 15 अगस्त तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय से इस अभियान की शुरुआत की। पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश व प्रदेशभर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि इस अभियान के दौरान भाजपा करीब 8 हजार बूथों पर 4 लाख भारतीय झंडे लगाने जा रही है, और इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान से नई पीढ़ी के साथ-साथ सभी आयुवर्ग के लोगों में देश व राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ेगा।

खेलकूद

सोलन ज़िले के अर्की में 14 वर्ष से कम आयुवर्ग के खिलाड़ियों की खेल प्रतियोगिता का मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने आज शुभारम्भ किया। इस प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के 2 सौ से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर खेल अधोसंरचना और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संजय अवस्थी ने हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी से प्रदेश सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग देने का आह्वान भी किया।

मछली उत्पादन

प्रदेश में वर्ष 2022-23 के दौरान 21 हजार मिट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में करीब 22 करोड़ 66 लाख रूपए की विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के प्रयासों से मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश के 6 सौ 82 युवाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खुले हैं। विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3 करोड़ रूपए से अधिक राशि की विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं।
